भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1232

उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

पंजाब में एआई की शिक्षा का आरंभ

†1232. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित पाठ्यक्रम आरंभ करने की पहल का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र प्रायोजित शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल शिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किसी सहायता की मांग की गई है या सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में डिजिटल अवसंरचना, स्मार्ट कक्षागृहों और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवंटित और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों के लिए एआई शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल साक्षरता पहलों, कोडिंग संबंधी गतिविधियों, आईसीटी सक्षम शिक्षा और शिक्षक क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत किया जा रहा है। समय-समय पर जारी पाठ्यक्रम और दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध डिजिटल शिक्षण प्लेटफार्मों और नवाचार-आधारित गतिविधियों के माध्यम से एआई से संबंधित जागरूकता और मूलभूत अवधारणाओं को एकीकृत किया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजनाओं समग्र शिक्षा और पीएम श्री को कार्यान्वित कर रहा है। मानदंडों के अनुसार मध्यवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न घटकों के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होता है। इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और योजना के कार्यक्रम और वित्तीय

मानदंडों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

सरकारी स्कूलों में एआई आधारित शिक्षण, एआई शिक्षण किट और शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पीएम श्री और समग्र शिक्षा के तहत वित्तीय सहायता के लिए राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

पंजाब सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में डिजिटल अवसंरचना और स्मार्ट कक्षाओं के लिए आवंटित और जारी की गई निधियां निम्न प्रकार है:

(लाख रुपए में)

वित्त वर्ष	**स्मार्ट कक्षाएं**		**आईसीटी प्रयोगशालाएँ**	
	आवंटित	**जारी**	**आवंटित**	**जारी**
2023-24	698.4	698.4	2,513.30	2,513.30
2024-25	36	36	343.7	343.7
2025-26	127.2	127.2	16,201.20	14,442.40
कुल	**861.6**	**861.6**	**19,058.20**	**17,299.40**

आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में 17 मई, 2020 को शुरू की गई एक व्यापक पहल पीएम ई-विद्या है, जो देश भर में शिक्षा तक बहु-प्रकार की पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग करने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। एनसीईआरटी इन पहलों की गुणवत्ता पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित मार्गदर्शन/प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है। पीएम ई-विद्या पहल में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं। पीएम ई-विद्या के हिस्से के रूप में, पंजाब राज्य को 5 चैनल (पीबी पीएम ई-विद्या 143 से 147) आवंटित किए गए हैं। राज्य द्वारा पंजाबी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम पर सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) सभी ग्रेडों के लिए क्यूआर कोड वाली एनर्जाइज्ड टेक्स्टबुक्स (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पहुंच में सहायता करता है, जिससे शिक्षार्थियों को इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना सामग्री डाउनलोड करने और अधिगम जारी रखने में सक्षम बनाया जाता

है, जिससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों के छात्रों के लिए एआई शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित होती है। वर्तमान में, दीक्षा के पास 9.4 + लाख नामांकन के साथ एआई और डिजिटल लर्निंग पर 59 पाठ्यक्रम हैं।

भारत सरकार ने बजट 2025 में, चरणबद्ध तरीके से दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने के लिए बीएसएनएल द्वारा 'भारतनेट' परियोजना के तहत पंजाब के 1,200 सरकारी ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है।

एआई और डिजिटल शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों के छात्रों के लिए, राज्य ने समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों में आईसीटी अवसंरचना और स्मार्ट क्लासरूम को मजबूत करने, दीक्षा और अन्य ई-सामग्री प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने, डिजिटल शिक्षाशास्त्र और उभरती प्रौद्योगिकियों पर शिक्षकों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने, स्कूल-स्तरीय गतिविधियों और नवाचार कार्यक्रमों के माध्यम से कोडिंग, नवाचार, एसटीईएम शिक्षा और एआई जागरूकता को बढ़ावा देने जैसे उपाय किए हैं।

इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर की एक पहल एसओएआर (एआई तत्परता के लिए कौशल) शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों सहित स्कूली छात्रों (कक्षा 6-12) के बीच एआई जागरूकता और मूलभूत कौशल को शामिल करना और शिक्षकों के बीच एआई साक्षरता का निर्माण करना है। एसओएआर में छात्रों के लिए तीन प्रगतिशील 15 घंटे के मॉड्यूल शामिल हैं - एआई जागरूक होना, एआई प्राप्त करना और एआई आकांक्षा करना - और शिक्षकों के लिए एआई फॉर एजुकेटर्स नामक एक स्वतंत्र 45 घंटे का मॉड्यूल। कार्यक्रम के तहत एआई की मूल बातें, जेनरेटिव एआई, दैनिक जीवन में एआई, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, नैतिकता, साइबर सुरक्षा और भविष्य के करियर के अवसरों जैसी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया जाता है।

*****